झुग्गी झोपड़ी कलस्टर/स्लम (31 जुलाई, 2013 तक की स्थिति)

- जितना भी झुग्गी–झोपड़ी का क्षेत्र है वह सब दिल्ली की काग्रेस सरकार के अधीन आता है। अतः सारी जिम्मेदारी उनकी है।

- दिल्ली की कुल आबादी का लगभग 50 प्रतिशत स्लम क्षेत्रों/अनाधिकृत कालोनियो और लगभग 860 झुग्गी झोपड़ी कलस्टरो में रहता है। यानि 2 करोड़ में से एक करोड़। जिन्हें मूलभूत सुविधाएं पानी, सीवर, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि भी प्राप्त नहीं है।

- मोटे तौर पर केवल 25 प्रतिशत लोग ही योजनाओं के अधीन विकसित क्षेत्रों में रहते हैं।

- वर्तमान स्थिति में महिलायें सबसे अधिक भुक्तभोगी हैं। जो बातें एक महिला को परिवार के जीवन में सुधार करने और उसे बेहतर बनाने में अपना योगदान करने से रोकती हैं, वे निम्नलिखित हैं :–

  (क)स्वरोजगार क्रिया कलापों में भाग लेने के संबंध में सीमित जानकारी होना।

  (ख)समुचित संसाधानों तक पहुंच सीमित होना (जैसे कि ऋण और कारोबार सहायता सेवायें)

  (ग)समन्वित सहायता प्रणाली और कार्यक्रम का अभाव।

  (घ)आय में वृद्धि करने के अवसरों से संबंधित समस्याओं के निदान के लिए अपनी आवश्यकताओं और मांगों के बारे में न बताना।

- वर्ष 2010 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के लिए निर्माण एवं सौंदर्यीकरण हेतु 22 स्लम/ झुग्गी बस्तियों को हटाया गया। आज तक उनका पुनर्वास नहीं हुआ है।

- केवल 20 प्रतिशत हटाये गये झुग्गी क्षेत्र को ही दिल्ली के अंतिम छोर पर बवाना में जगह दी गई जहां कोई भी जनसुविधायें आज तक उपलब्ध नहीं हैं। 22 बड़ी स्लम बस्तियों की 80 प्रतिशत आबादी को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। न सड़के न सीवर न पानी न बिजली।

शौचालय – महिलाओं और बच्चों को शौच के लिए खुले में जाना पड़ता है।

- झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में शौचालय और स्वच्छता संबंधी समस्यायें विकट हैं। इन झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में लोगों को खुले मैदान में शौच करना पड़ता है और महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ती है।

- दिल्ली में सार्वजनिक शौचालयों में से केवल 4 प्रतिशत में ही महिलाओं के लिए ही इस्तेमाल किये जा सकते हैं।

- सेन्टर फॉर सिविल सोसाइटी के अनुसार दिल्ली में महिलाओं के लिए केवल 132 सावर्जनिक शौचालय हैं और झुग्गी बस्तियों में तो इनकी संख्या और भी कम है।

- इससे महिलाओं को अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है जैसा कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में महिलाओं के विरूद्ध हुये अपराध की अनेक घटनाओं से पता चलता है।

- सुरक्षा की समस्या के अतिरिक्त शौचालयों की कमी से इन कालोनियों में स्वास्थ्य को भी खतरा रहता है।

- दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी बस्तियों और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले 56 प्रतिशत बच्चे सार्वजनिक शौचालयों के अभाव में खुली जगह में ही शौच करते हैं।

- तीन वर्ष से कम आयु के 79 प्रतिशत बच्चे शौच करने के लिए खुली जगह का उपयोग करते हैं।

- इनमें से तीन वर्ष से अधिक आयु की 56 प्रतिशत लड़कियां खुले स्थान पर शौच करने के लिए बाध्य होती हैं और तीन वर्ष से अधिक आयु के 48 प्रतिशत लड़कों को सार्वजनिक शौचालयों की सुविधा नहीं है।

- झुग्गी झोपड़ी कलस्टरों में शौचालय ब्लाकों की कमी और मौजूद शौचालयों में स्वच्छता न होने के कारण झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को खुले स्थानों में ही शौच करना पड़ता है जिसके फलस्वरूप प्रदूषण होता है और बीमारियां फैलती हैं।

सुरक्षा– पुलिस झुग्गीवासियों को सुरक्षा देने की जगह तंग करती है।

- एक गैर सरकारी संगठन नवसृष्टि द्वारा सूचना के अधिकार के अधीन पूछे गये प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया कि वर्ष 2011 में राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन 13 बच्चे गुम होते हैं। इनमें से अधिकांश बच्चे स्लम बस्तियों के होते हैं।

- वर्ष 2011 के अंत तक 11,00 से अधिक बच्चों का कोई पता नहीं चला।

- जनवरी से जून, 2012 में 1,000 बच्चे गुम हुये थे। इनमें से अधिकांश बच्चे दिल्ली की स्लम बस्तियों के परिवार के थे।

- महिलाओं के लिए समुचित सुविधायें न होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है और वे घरों में भी सुरक्षित नहीं हैं।

शिक्षा – दिल्ली की स्लम बस्तियों में शिक्षा से संबंधित समस्यायें :–

(क) दिल्ली के सरकारी विद्यालयों तक दाखिले के लिए पहुंच भी नहीं पाते।,
(ख) दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता की कमी, शिक्षा प्राप्त करने में छात्राओं को बहुत दिक्कतें शौचालयों के कारण भी।
(ग) बीच में विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्र/छात्राओं की अधिक संख्या।

- शिक्षकों की कमी है और जो शिक्षक कार्यरत हैं उनमें प्रतिबद्धता की कमी एक बड़ी समस्या है।

- माता–पिताओं की भी यह राय है कि इन विद्यालयों में पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम स्लम बस्तियों के बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है।

- दिल्ली की स्लम बस्तियों में रहने वाली लगभग 75 प्रतिशत लड़कियां 18 वर्ष से पूर्व ही शादी कर लेती है। इसके विपरीत दिल्ली में केवल 6.7 प्रतिशत लड़कियां ही 18 वर्ष के पूर्व शादी करती हैं।

- स्लम बस्तियों में रहने वाले अब 600 से 1000 रूपये तक बिजली के लिए भुगतान करते हैं जबकि भाजपा शासन में जब साहिब सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब 15 रूपये प्रति प्वाईंट की दर से केवल भुगतान करना होता था और इस प्रकार दो प्वाईंट के लिए केवल 30 रूपये देने होते थे।

- स्लम बस्तियों में रहने वाले लोगों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है और उन स्कूलों में जहां बच्चे स्कूल जाते हैं, मूलभूत सुविधायें नहीं हैं जिसके फलस्वरूप बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं।

पानी–सीवर

- स्लम बोर्ड 100 झुग्गियों के लिए केवल एक पानी की टूटी उपलब्ध कराता है अन्य लोग झुग्गियों की मेन लाइन से पानी निकालने को मजबूर है जिसके कारण मेन लाइन से पानी चला जाता है या गंदा पानी आता है।

- झुग्गी झोपड़ी कलस्टरों में सीवेज उपलब्ध कराना एक बड़ी समस्या है। सीवेज लाइनों और नालों के अभाव में सारा कलस्टर एक गंदे तालाब में बदल जाता है और जब मानसून आता है तो झुग्गियां कई फीट पानी में डूब जाती हैं।

राशन

- दिल्ली को मिट्टी तेल मुक्त शहर बनाने के नाम पर दिल्ली सरकार ने मिट्टी तेल की बिक्री बंद कर दी है किन्तु आधे लोगों को भी गैस सिलेण्डरों की सप्लाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की है।

- एक और समस्या यह है कि सब्सिडी प्राप्त गैस सिलेण्डर की कीमत 412 रूपये है। इसकी तुलना में 14.83 रूपये प्रति लीटर की दर से प्रतिमाह 12.5 लीटर मिट्टी के तेल पर कुल खर्च इसका आधा ही बनता था।

- झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग 15 किलो के सिलेण्डर जिनकी कीमत 25 रूपये किलो हैं नहीं खरीद पाते, वे 4 किलो के सिलेण्डर खरीदते हैं जिसकी कीमत 100 से 120 रूपये किलो होती है।

- दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी में 6 लाख 26 हजार 760 बी.पी.एल. (ए.ए.वाई.) ए.पी.एल. (जे.आर.सी.), आर.सी. के कार्डधारक हैं। क्या आप जानते हैं कि दिल्ली में एक लाख तक की आमदनी वाले 15 लाख 85 हजार 50 लोगों को दिल्ली में पिछले 15 साल से राशन नहीं मिलता।

- दिल्ली में राशन बांटने की व्यवस्था (पी.डी.एस सिस्टम) वधवा कमेटी के अनुसार पूरे देश में भ्रष्टाचार में दूसरे नम्बर पर है।

- दिल्ली में दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कोरपरेशन राशन देने का काम न करके शराब के ठेके खोलने का रिकार्ड बना रहा है।

- फूड सिक्योरिटी बिल में चुनाव को देखते हुए अब कांग्रेस सरकार को 90 लाख लोग गरीब नजर आ रहे हैं। किन्तु इससे पहले 6 लाख को भी मुश्किल से राशन मिल रहा था।

- जानकारी के अनुसार एफ.सी.आई. गोदामों से सप्लार्अ किए जाने वाले गेहूँ, चावल का ट्रक सीधे बाजार में बेच दिया जाता है। जो दुकान तक नहीं पहुंचता। भाजपा शासन में ट्रक का पीछा सिविल सप्लाई का बिजिलैंस विभाग पीछा करता था। समय–समय पर कार्यवाही होने से लोगों में डी पैदा होता था। जिससे इस प्रकार की कालाबाजारी को रोका जा सकता है।

झुग्गी–झोपडी से झूठे वायदे

- पिछले विधानसभा चुनाव के पूर्व कांग्रेस ने झुग्गी झोपड़ी वासियों को फ्लैट देने का झूठा वायदा किया था और लाखों लोगों ने राजीव रत्न आवास योजना के अधीन फार्म भरे थे। अब तक किसी भी झुग्गी झोपड़ी वासी को न तो फ्लैट मिले हैं और न ही उन स्थानों पर मकानों का निर्माण हुआ है जहां झुग्गी झोपड़ियां थीं।

- जबकि वर्ष 1993 से 1998 में भाजपा शासन के दौरान प्रत्येक झुग्गी झोपड़ी कलस्टर में बस्ती विकास केन्द्र था जिसमें रोजगार पाने के लिए शिक्षा, कौशल और प्रशिक्षण देने की व्यवस्था थी। इन केन्द्रो का उपयोग समुदाय केन्द्र के रूप में भी किया जाता था जिसमें शादियां तथा अन्य सामुदायिक कार्यक्रम होते थे।

- झुग्गी झोपड़ीवासी, कल्याणकारी योजनाओं के ठीक ढंग से लागू न होने के बारे में यह कह कर शिकायत करते रहे हैं कि उन्हें अपने अधिकारों और राशन कार्ड, पेंशन, मतदान पहचान पत्रों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है।

- रोहिणी सेक्टर–4 में 2,400 एक कमरे वाले डीडीए फ्लैट भ्रष्टाचार के कारण कई महीनों से खाली पड़े हैं हालांकि वे कब्जे दिये जाने के लिए तैयार हैं। ये फ्लैट मोतियाखान झुग्गी झोपड़ीवासियों के पुनर्वास के लिए बनाये गये थे। मोतियाखान में रहने वाले 1,770 पात्र परिवार अभी तक 1990 से अपने भाग्य के भरोसे बैठे हैं।

- झुग्गी–झुोपडियों से धोखा करते हुए तीन बस्तियों कठपुतली कालोनी, गोविंदपुरी कॉलोनी, कुसुम पुर पहाड़ी कालोनी में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने शिलान्यास के बोर्ड लगा दिये पर एक भी फ्लैट नहीं बना।

सीएजी रिपोर्ट : 2011–12

- सीएजी की रिपोर्ट में शहरी गरीबों के लिए मूलभूत सुविधायें कार्यक्रम (बीएसयूपी) के अधीन 4 लाख सस्ते मकान बनाने के लक्ष्य को पूरा न करने के लिए दिल्ली सरकार की निंदा की गई है।

- 4 लाख घरों के लक्ष्य में से केवल 1.1 लाख यूनिटें ही मार्च, 2012 तक स्वीकृत हो पाई थीं। यह योजना और भी छोटी हो गई जब भूमि की कमी के कारण 44,720 यूनिटें इसमें से हटा दी गईं।

- 10,684 निर्मित यूनिटों में से 85 यूनिटें ही लाभार्थियों को आबंटित की गईं। यह कटौती जारी रही क्यों कि 31 मार्च, 2012 तक 20,340 यूनिटों के लिए कार्य का ठेका अभी दिया जाना बाकी है।

- 1200 यूनिटों की एक और परियोजना दिल्ली अर्बन सेल्टर इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड (डीयूएसआईबी) द्वारा निविदा को अंतिम रूप न दिये जाने के कारण विलम्ब होने से छोड़ दी गई।

- डीयूएसआईबी द्वारा राष्ट्रीय भवन निर्माण मानकों का पालन न किये जाने के कारण 9,780 यूनिटों का निर्माण बीच में ही छोड़ दिया गया।

- सीएजी ने यह भी बताया कि अप्रैल, 2011 और मार्च, 2012 के बीच डीयूएसआईबी ने एक भी यूनिट पूरी नहीं की जबकि विभिन्न परियोजनाओं पर उसने 74.2 करोड़ रूपये खर्च किये।

- डीयूएसआईबी ने 24,076 यूनिटों के निर्माण की 8 परियोजनायें अनुमादित की जिसकी कुल लागत 1,102 करोड़ रूपये थी, सीएजी ने इसकी कठोर आलोचना की।

- डीयूएसआईबी ने 5,872 यूनिटों के निर्माण कार्य को छोड़ने के बाद केवल 1,024 यूनिटों का निर्माण ही पूरा किया। इन यूनिटों का निर्माण दिसम्बर, 2011 में ही पूरा हो गया था। किन्तु मई, 2012 तक भी इनमें घरेलू उपयोग के लिए पानी की सप्लाई नहीं दी गई।

- विशेषज्ञता की कमी : सीएजी ने यह नोट किया है कि डीयूएसआईबी को शहरी गरीबों के लिए जेएनएनयूआरएम के अधीन निर्मित मकानों का आबंटन करने के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया था किन्तु उसके पास इस कार्य को पूरा करने के लिए विशेषज्ञता और तंत्र का अभाव था।

- डीएसआईआईडीसी द्वारा 14 परियोजनाओं के अधीन 81,528 यूनिटों के लक्ष्य में से केवल 9,660 यूनिटें ही निर्मित हो पाई हैं जिसकी लागत 3,007.34 करोड़ रूपये थी। 40,048 यूनिटों का निर्माण कार्य छोड़ दिया गया।

- सीएजी ने डीएसआईआईडीसी की इस बात के लिए आलोचना की है कि उसने एक परियोजना के लिए पुनः टेंडर नहीं मंगवाया जिसके लिए केवल एक ही टेंडर आया था और जिसके लिए उसने दोगुनी राशि का टेंडर दिया था।

भाजपा सत्ता में आएगी तो झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए जो योजनायें चल रही हैं उसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य करेगी

मकान

- भाजपा हर झुग्गीवासी को जहां उसकी झुग्गी बनी हुई है, वहीं पर पक्के फ्लैट बनाकर देगी। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप नियम के तहत जल्दी से जल्दी फ्लैट बनाने का काम पूरा किया जाएगा, जैसा मुम्बई में है।

- जिन झुग्गीवासियों ने राजीव रत्न आवास योजना के नाम पर सस्ते मकान के लिए फार्म भरा था, और कांग्रेस सरकार ने उन्हें फ्लैट नहीं दिया, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर फ्लैट दिया जाएगा।

बिजली

- हर झुग्गीवासी को बिजली प्वाइंट के हिसाब से सस्ती बिजली दी जाएगी, जैसे भाजपा के शासनकाल में जब साहिब सिंह जी मुख्यमंत्री थे, पंद्रह रूपए प्रति प्वाइंट के हिसाब से तीस रूपए में दो प्वाइंट मिलते थे।

राशन

- भाजपा सत्ता में आएगी तो नए राशन कार्ड बनाने तुरन्त शुरू कर देगी, जो 8 साल से कांग्रेस सरकार में बन्द कर दिए गए थे।

- जिन झुग्गीवासियों के पास बीपीएल के कार्ड नहीं हैं, उन सभी को बीपीएल के कार्ड बनाकर दिए जाएंगे जिनकी संख्या लाखों में हैं, जिससे उन्हें सस्ता राशन मिल सके और गेहूं, चावल के साथ हम दालें, खाद्य तेल भी देंगे।

- गैस चूल्हा और सिलेंडर सभी झुग्गीवासियों को मुफ्त में दिया जाएगा। जो झुग्गी निवासी बड़ा सिलेंडर लेने में असमर्थ रहते हैं और चार किलो का सिलेंडर बाजार से सौ–एक सौ बीस रूपए किलो में भरवाते हैं। भाजपा सत्ता में आएगी तो चार किलो का छोटा सिलेंडर भी सरकारी रेट पर मिलेगा।

सीवर–शौचालय

- सभी झुग्गी बस्तियों में सीवर लाईन डालकर पानी की निकासी की व्यवस्था की जाएगी।

भाजपा सत्ता में आएगी तो झुग्गी बस्तियों के विकास के लिए जो योजनायें चल रही हैं उसके अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य करेगी

- नए टॉयलेट ब्लॉक बनाए जाएंगे और उनकी सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएगा।

पानी

- हर झुग्गी को पानी का कनैक्शन दिया जाएगा, जिसमें साफ पानी उपलब्ध होगा।

बस्ती विकास केन्द्र

- प्रत्येक झुग्गी बस्ती में बस्ती विकास केन्द्र बनाया जाएगा, जिसमें सिलाई–कढ़ाई, मोबाइल व कम्प्यूटर रिपेयरिंग के अलावा स्वरोजगार हेतु अन्य प्रशिक्षिण दिए जाएंगे और लोग अपने बच्चों की शादी एवं अन्य आयोजन यहां पर कर सकेंगे।

स्वास्थ्य

- चिकित्सा सुविधा हेतु डिस्पेंसरियां खोली जाएंगी व मोबाइल डिस्पेंसरी वैन उपलब्ध कराई जाएगी।

सुरक्षा

- झुग्गी बस्तियों में जो छोटे बच्चे गुम हो रहे हैं, उनको पुलिस बूथ बनाकर सुरक्षा दी जाएगी।

शिक्षा

- सरकारी स्कूल पब्लिक स्कूल की तरह बनाए जाएंगे, जिसमें अंग्रेजी पर जोर होगा और खिलौनों के माध्यम से पढ़ाई होगी।
- नए सरकारी स्कूल खोले जाएंगे।
- पहले से आईएएस तक की परीक्षा की पुस्तक निःशुल्क सभी झुग्गी वालों के बच्चों को मिलेंगी।
- गरीब बच्चों के लिए स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेलने की सस्ती सुविधा होगी।